











## NEWS इन ब्रीफ

जंगली हाथियों ने घर

को उजाड़ा और

आनाज कर गये चट

बोलबा। बोलबा प्रखण्ड के

अवामा बाजार टोली में जंगली

हाथियों ने एक घर को उजाड़ा

और अनाज खा गए। इस

मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि

बीती रात के लगभग 10:00

बजे बिछड़े हुए एक हाथी ने

गांव पहुंच गया और महावीर

प्रधान के घर के खपड़ेल छत

को उजाड़ा एवं वहां पर रख दें

एक बोरी चावल को खा गया।

ग्रामीणों ने एक जुट होकर उस

हाथी की जंगल की ओर

भगाया। इसके बाद जंगली हाथी

ने बरटोली गांव में मगरीता

विठ्ठुन के घर भी उजाड़ा

दिया। इस दौरान घर में रखे

अनाज को खा गया। ग्रामीणों ने

हाथियों को भासाने मुआवजा की

मांग बन विभाग से किया है।

निर्माण कार्य में  
अनियमितता की  
शिकायत

ठेठ्ठिंगर। प्रखण्ड के कोनपाला में

कोनपाला से पाकरीटोली तक बन

रह सड़क सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य

में हो रही अनियमितता की

शिकायत पाप ठेठ्ठिंगर पश्चिमी जिला

सदस्य अजय एकवा कार्य स्थल

पहुंचकर उहोने निर्माण कार्य से

संबंधित आवश्यक बिंदुओं का

निरीक्षण करते हुए जानकारी ली।

ग्रामीणों ने बताया कि सड़क

सुदृढ़ीकरण कार्य में पूरी तरह से

अनियमितता भरती जा रही है। इसमें

बहुत ही धृतिया की सामीक्षा

स्तम्भ की जा रही है, जो बोर्टर

स्तम्भ की जा रही है वही

घटिया किसी की है रोलर चलने के

साथ साथ चूर्चा हो जा रही है।

ग्रामीणों ने वही भी बताया कि

निर्माण कार्य अन्तर्वाही गुणवत्ता हो रही है।

जिसकी जांच होनी चाहिए। एवं गुणवत्ता पूर्ण निर्माण होनी चाहिए।

मौके पर जिप सदस्य

अजय एकवा ने कहा कि इन्होंने

घटिया किसी का बादशह नहीं करें।

इसकी शिकायत विभाग एवं

उपायुक्त से करेंगे एवं जांच की मांग

करेंगे मौके पर जिप सदस्य

प्रतिनिधि अमृत चिराग तिर्की,

दानशील एकवा आदि उपस्थित थे।

बीआरसी में बच्चों  
को दिया गया  
चरमा

बोलबा। बोलबा प्रखण्ड मुख्यालय

रित बीआरसी में बच्चों को दिया गया

चरमा इस मौके पर बताया गया कि

स्कूलिंग कार्यक्रम के दस विद्यालय

के कुल इक्सर बच्चों को चरमा वितरण किया गया।

जिसमें रातम विद्यालय बेलुक्या

को एक, राम विद्यालय आवामा को नौ,

आरसी प्राथमिक विद्यालय मालसाडा

को एक, आरसी मध्य विद्यालय

पीडियोंपें को चौदह, आरसी सी

प्राथमिक विद्यालय खंडिनशनं को

एक, कस्तुरा गांधी विद्यालय बोलबा

को सोलह, अरनीवनीबासा को

एक, ऐस एस उच्च विद्यालय बोलबा

ग्याह, आरसी बालिका समस्तरा को

चार, राम विद्यालय पाकबहार को तीन

चरमा दिया गया। बताया गया कि

प्रखण्ड के कुल दस विद्यालय के

इक्सर छात्रों को चरमा का वितरण

किया गया। इस मौके पर मुखिया

सुरजन बडाईक ने कहा गया कि

सरकार की वह महत्वपूर्ण योजना है।

# राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा बजट में टेक्नोलॉजी के साथ मानव स्पर्श को प्राथमिकता

एवं जीवी। नई दिल्ली



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि उनके सरकार ने हर बजट में प्रौद्योगिकी की मदद से देशवासियों के जीवन बापन को सरल बनाने पर जोर दिया है और इस बार के बजट में प्रौद्योगिकी के साथ ही मानव स्पर्श को प्राथमिकता दिया गया है। मोदी ने अगले वित्त वर्ष के बजट में एक बार भी की कड़ी के आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर मानव स्पर्श को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। इस बार के बजट में भी सरलता विषय पर वेबानार को संबोधित करते हुये कहा कि 21वीं उन्होंने कहा एक जमाना था जब हमारे देश में सरकार की सेलगातार सशक्त कर रहा है। वीते

**ज्ञानरण्ड सरकार**  
ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्य अभियंता का कार्यालय,  
102, द्वितीय तला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, राँची

पत्रांक- दिनांक-  
निविदा स्थगन संबंधित सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गढ़वा के निविदा आमंत्रण संख्या- 281/2022-23/RWD/GARHWA, दिनांक- 09.02.2023, PR NO.-289832 के द्वारा प्रकाशित निविदा में आईडेन्टीफिकेशन संख्या- RWD/GARHWA/36/SPKG-01/2022-23 की निविदा को परिणाम विषय (Bill of Quantity) पर अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण स्थगित किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी  
PR 291471 (Rural Work Department) 22-23 (D)

ई-प्रोकर्नेट सेल

**ज्ञानरण्ड सरकार**  
ग्रामीण कार्य विभाग, मुख्य अभियंता का कार्यालय,  
102, द्वितीय तला, अभियंत्रण भवन,  
कचहरी रोड, राँची

पत्रांक- दिनांक-  
निविदा स्थगन संबंधित सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, राँची के निविदा आमंत्रण संख्या- 278/2022-23/RWD/RANCHI, दिनांक- 09.02.2023, PR NO.-289826 के द्वारा प्रकाशित निविदा में आईडेन्टीफिकेशन संख्या- RWD/RANCHI/47/SPKG-01/2022-23, RWD/RANCHI/48/SPKG-02/2022-23, RWD/RANCHI/49/SPKG-03/2022-23, RWD/RANCHI/50/SPKG-04/2022-23 एवं RWD/RANCHI/51/SPKG-05/2022-23 की निविदा को परिणाम विषय (Bill of Quantity) पर अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण स्थगित किया जाता है।

नोडल पदाधिकारी  
ई-प्रोकर्नेट सेल

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय**  
**लघु सिंचाई प्रमण्डल, मेदिनीनगर**

e-mail I.D. - eemidmed-cemr-jhr@nic.in, 06562-240100 (का)

पत्रांक-129/ मेदिनीनगर, दिनांक- 25.02.2023 /

**निविदा रद्द संबंधी सूचना**

इस कार्यालय का पत्रांक-883, दिनांक-22.10.2022 के द्वारा आमंत्रित ई0-निविदा आमंत्रण सूचना सं0-WRD/MID/MEDININAGAR/F2-14/2022-23 जिसका PR No.-280753 Water Resource (2022-23) D है, निविदा को अपरिहार्य कारणवश रद्द किया जाता है।

कार्यपालक अभियंता  
लघु सिंचाई प्रमण्डल, मेदिनीनगर

PR 291440 (Water Resource)22-23\*D

**पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, लातेहार**  
- : आवश्यक सूचना :-

लातेहार जिला अंतर्गत हेरहं थाना कांड सं0-34/17, दिनांक-16.10.2017, धारा-147/148/149/353/324/307 भा020 वि. 27 आन्सर एक्ट एवं 13 यूए०पी एक्ट के प्राथमिकी अभियुक्त रौशन जी उर्फ रौशन उरांव उर्फ दशथ उरांव पै. स्व० धनू उर्वै सा० सुईयांटांड थाना टंडवा, जिला चतरा के विरुद्ध अनुसंधान के क्रम में उक्त काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध विधिवत इशितहार तामिला किया गया है। उक्त प्राथमिकी अभियुक्त के विरुद्ध इशितहार तामिला पश्चात् कुर्की अधिपति प्राप्त किया जाएगा। उक्त से संबंधित सूचना प्रचार-प्रसार हेतु प्रकाशित किया जा रहा है।

क्रम अभियुक्त का नाम एवं पता

1. रौशन जी उर्फ रौशन उरांव उर्फ दशथ उरांव पै.

स्व० धनू उर्वै सा० सुईयांटांड, थाना टंडवा, जिला चतरा

60/-

PR.NO.291406 Police(22-23):D

पुलिस अधीक्षक, लातेहार।

विरोधाभास नजर आता था। समाज का एक वर्ग ऐसा था, जो चाहता था कि उनके जीवन में हर कदम पर सरकार का कोई हस्तक्षेप हो, सरकार का प्रभाव हो, यानी स्थिति बदलने लगी है। आज सरकार उनके लिए कुछ न कुछ करे। लेकिन पहले की सरकारों के मामलों में हर बजट में जीवन यानी सरकारात्मक प्रभाव हर उस जगह दिखने लगा है जहां इसकी सबसे महसूस किया। अभाव में जिंदगी जूनों में ही निकल जाती थी। समाज में ऐसे लोगों का भी वर्ग था, यह दूर्घे प्रकार का था। जो स्वयं उनके सरकारों के समर्थन से आगे बढ़ा चाहता था, उनके सरकारों को जीवन यानी सरकार का बदलता हुआ भारत, अपने उन्होंने कहा एक जमाना था जब हमारे देश में सरकार की प्राथमिकताओं में बहुत ज्यादा

सरकारी दखल भाँति-भाँति की रूकावटें डग-डगर पर महसूस करता रहा। हमारी सरकार के बीते कुछ वर्षों के प्रयासों से अब ये स्थिति बदलने लगी है। आज सरकार की नीतियों और नियन्यों का सकारात्मक प्रभाव हर उस जगह दिखने लगा है जहां इसकी सबसे महसूस किया। अभाव में जिंदगी मिलने जूनों में ही निकल जाती थी। समाज में ऐसे लोगों का भी वर्ग था, यह दूर्घे प्रकार का था। जो स्वयं के समर्थन से आगे बढ़ा चाहता था, उनके सरकारों के दखल और दबाव भी कम हो गया है।

## पुलिस अधीक्षक का कार्यालय गढ़वा

### आवश्यक सूचना

(लापता लवकेश कुमार राम, उम्र-28 वर्ष लगभग)



मेराथा थाना दैनिकी सनहा सं0-12/23, दिनांक-22.02.2023 में लापता लवकेश कुमार राम, उम्र-28 वर्ष लगभग, पिता-हरिहर राम, ग्राम-गोरुआ, पौ-देवगाना, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा, राज्य-झारखण्ड, के रहने वाला है। जो दिनांक-18.02.2023 को रात्री में 10:30 बजे घर पर बिना किसी को बताये कहीं चला गया है। उक्त लापता का काफी खोजबीन किया गया परन्तु अबतक पता नहीं चल सका है। अतः आम जनता से अनुरोध है कि लापता लवकेश कुमार राम के बारे में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की सूचना प्राप्त हो तो पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) गढ़वा के मोन०-9431706284 या पुलिस अधीक्षक, गढ़वा के मोन०-9431706281 पर सूचित करने की कृपा करें।

हुलिया:-  
रंग-गोरा, लम्बाई-05 फीट 04 इंच,  
पहनावा-काला रंग का ईनर एवं  
कमीज हल्का सफेद जिसमें हरा रंग की धारी है।

निवेदक,

पुलिस अधीक्षक, गढ़वा

PR 291453 Police(22-23)#D

### NAGAR PANCHAYAT, SHRI BANSHIDHAR NAGAR

Nagar Panchayat Office, Shri Banshidhar Mandir road, Shri

Banshidhar Nagar, District- Garhwa. Jharkhand - 822121

Phone No.: 776398693 email ID: npnagaruntari@gmail.com

(NIT No. 10/2022-23)

Reference No. - ULB/NIT/SHRI BANSHIDHAR NAGAR SEPTAGE/TENDER/1910/2022/ 109 Date: 23-02-2023

### Short Term Tender Notice, IMPORTANT INFORMATION

#### 1 Name of Work

Construction and Commissioning of Faecal Sludge Treatment Plant of Capacity 6 cum/day at Shri Banshidhar Nagar town (Jharkhand) followed by Operation and Maintenance including desludging operations for 5 years

#### 2 Estimated Cost (INR)

Construction Cost: ₹1,36,52,734/-

Operation & Maintenance Cost: ₹87,57,955/-

#### 3 Bid Security (INR)

Total: ₹2,24,10,689/- ₹2,24,000/- (Rupees)

#### 4 Cost of Bid Document (INR)

₹10,000/- (Rupees Ten Thousand Only); non-refundable

#### 5 Time of Completion

1 year of construction which comprises 9 months of construction and 3 months of defect liability period including one month of trial run and 5 years of O&M post DLP

#### 6 Date of e-publication of tender

23-02-2023, 14:00 Hrs

#### 7 Document downloading start Date

23-02-2023, 16:00 Hrs

#### 8 Start date for seeking clarification

23-02-2023, 16:00 Hrs

#### 9 End date for seeking clarification

28-02-2023, 17:00 Hrs

#### 10 Pre bid meeting date, Time & Venue

27-02-2023, 14:00 Hrs at Chamber of Office of Executive Officer, Nagar Panchayat Office, Shri Banshidhar Nagar Mandir road, Shri Banshidhar Nagar, Distt. Garhwa, Jharkhand - 822121.

#### 11 Bid submission end date

11-03-2023, 17:00 Hrs

#### 12 Last day for the submission of Bid Security, cost of bid document

13-03-2023, 16:00 Hrs

#### 13 Bid opening date (online)

Complete bid document is available on website <http://jharkhandtenders.gov.in> other details can be

## सदन की मर्यादा

झारखंड में बजट सत्र की शुरूआत हो चुकी है। इसे लेकर सभी दलों में मगजमारी जारी है। ऐसा देखा जाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी बातों को रखने की बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यह गलत परम्परा है। इससे बचते हुए लोकउपयोगी और जनकल्याण की बातों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। ऐसा देखा जा रहा है कि हंगामा करने और नहीं करने वाले दोनों यह जरूर जानते हैं कि यह गलत परम्परा है। पक्ष और विपक्ष के अपने-अपने तर्क हैं। इन तर्कों की पाठशाला में सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने से बाज नहीं आते हैं। अगर तर्कों पर बात हो, तो यह ठीक है। यह जानना और समझना जरूरी है कि बजट सत्र कई मायने में महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा बनती है। साथ ही सालभर के विकास कार्यों की रूपरेखा भी तय होती है। इस सत्र में कई विधेयकों के पेश होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा हो जाये तो राज्यपाल को आपत्ति करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। बहुत दिनों बाद लंबे सत्र का आयोजन किया जा रहा है। विधायक जरूरी बातों को सदन के सामने रखें। ऐसे में सकारात्मक तरीके से शामिल होना जरूरी है।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की जमकर तारीफ की और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने झारखंड के शहीदों को नमन किया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया।

राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के अधिभाषण के साथ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल ने अपने अधिभाषण में राज्य सरकार की जमकर तारीफ की और सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने झारखंड के शहीदों को नमन किया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा भाषण अग्रेजी में दिया। राज्यपाल ने कहा कि रांची स्थित विरसा मुंदा एयरपोर्ट का विस्तार किया जायेगा। इसके अलावा धनबाद, गुपला और लोहरदगा में नये समाहरणालय के निर्माण की भी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि झारखंड के विकास में आप अपनी भूमिका निभायें। बहरहाल यह सही है कि राज्य सरकार ने जितना काम कोविड रोकथाम, कोविड अनुकूल व्यवहार और अस्पताल प्रबंधन के लिए किया उतना ही काम गरीबों की रोजी रोटी, बच्चों की शिक्षा, युवाओं के रोजगार, विकास के काम और जन कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए भी किया है। यह दोगों बात है कि यहां के आला अधिकारी विकास योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में असफल साबित होते दिख रहे हैं। यह समझना जरूरी है कि लोकतंत्र की सार्थकता जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन में निहित है। अब यह अधिकारियों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह सरकार के कामों को जन-जन तक पहुंचाने का काम करें। बहरहाल सदन से काफी उम्मीदें हैं। आशा है सदन की मर्यादा की रक्षा होगी।

लम्बे समय की शांति, अमन-चैन एवं खुशहाली के बाद एक बार फिर कश्मीर में अशांति एवं आतंक के बादल मंडगाने लगे हैं। धरती के स्वर्ग की आभा पर लगे ग्रहण के बादल छंटने लगे थे कि एक बार फिर कश्मीर के पुलवामा के अचन गांव में एक कश्मीरी पीड़ित की हत्या ने अनेक सवाल खड़े कर दिये हैं। सवाल अनेक हैं लेकिन एक ज्वलातं सवाल है कि क्या कश्मीरी पीड़ितों की हत्याओं के सिलसिले

का कभी अंत हो पायेगा? क्या अचन गांव में एक और कश्मीरी पंडित की हत्या भी अखबारों और टीवी चैनलों की सुरिख्यां बनकर ही रह जायेगा? क्या कश्मीर घाटी का अमन-चैन वापस लौटेगा? कश्मीर पहले की तरह धरती का स्वर्ग नजर आयेगा? इन सवालों का जवाब सिर्फ कश्मीर की जनता ही नहीं, बल्कि देश के साथ पूरी दुनिया भी जानने को उत्सुक है। यह सही है कि घाटी में सुरक्षा बलों और सैन्य ठिकानों पर हमले अब काफी कम हो गये हैं, लेकिन आप नागरिकों और खासकर कश्मीरी पंडितों और प्रवासी कामगारों की सुरक्षा से जुड़े सवाल अब भी अहम एवं कायम हैं। बीते साले तीन दशक के दौरान कश्मीर का लोकतंत्र कुछ तथाकथित नेताओं का बंधुआ बनकर गया था, जिन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिये जो कश्मीर देश के माथे का ऐसा मुकुट था, जिसे सभी प्यार करते थे, उसे डर, हिंसा, आतंक एवं दहशत का मैदान बना दिया। वैसे तो कश्मीर अनेक बार जंग का मैदान बनी है, लेकिन इस बार चुनाव का मैदान है। बुलंट की जगह हैं बैलंट। जंग कोई भी हो खतरा तो उठाना ही पड़ता है। जंग कैसी भी हो, लड़ता पूरा राष्ट्र है। भारत की इज्जत और प्रतिष्ठा है कश्मीर, नाक है। कितनी कीमत चुका दी, चुका रहे हैं। वहां राजनीतिज्ञों की माँग है—स्वायत्ता। जनता ही माँग है—शांति। दोनों चाहते हैं वहां लोकतंत्र लौटे। दोनों को इन्तजार है नतीजों का। इधर पूरे राष्ट्र व विश्व को भी इन्तजार है नतीजों का। तीन दशकों

# क्या कश्मीर में बदलते हालात जंग की आहट है?



लालत ग

विफल है और वे फिर पलायन का सोच सकते हैं। पर यह आतंक व खाद-पानी देने जैसा होगा। आतंक के पोषक और उनके आका भी यदि चाहते हैं कि ठर कर घर घाटी में बचे खुचे पंडित भी पलायन कर जाएँ और दशकों पहले घर-बार छोड़कर भाग चुके पंडित घर वापसी वे बारे में कर्तव्य न सोचें। यह तो जीव की ओर बढ़ते कदमों के पीछे हटके जैसे हालात है। सरकार घर-बार छोड़कर भाग चुके पंडितों की घाटी में वापसी चाहती है। पर वे लोगों जिन्होंने नब्बे के दशक में आतंक के दौर में भी घाटी नहीं छोड़ा, अब चुन-चुन कर मारे जा रहे हैं तो जम्मू या देश के अन्य हिस्सों में रहे पंडितों को वापसी के लिए कैसे मनाया जा सकता है। असुरक्षा व भावना अब भी उत्तरी ही है, जितना पहले थी। हमारे लिए कश्मीर सिपाही जमीन का एक टुकड़ा मात्र नहीं है यह हमारी शान है, इससे हमारी भावनात्मक एवं राष्ट्रीय युद्धाव है पुलवामा में सैनिकों पर हो चुका अमरनाथ यात्रियों पर, दिमाग़ कौंध रहे सवाल और बड़े होकर उमड़ने लगते हैं। यह सही है विद्या आतंकी घटनाएँ पूरी दुनिया के लिए चुनाती बनी दुई हैं, लेकिन क्या हाल कश्मीर में इसे जड़ से उखाड़ नहीं फेंक सकते? आतंककारों घटनाओं पर देश में होने वाली राजनीति भी इस दिशा में नकारात्मक पहलू माना जा सकता है। सब जानते हैं कि पिछले साल तीन दशक में दिल्ली और कश्मीर की सत्ता पर भाजपा भी काबिली रही है और कांग्रेस भी।

# नई सीएसआर निगरानी नीति की जरूरत

भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां कॉरपोरेट सोशल रिस्पार्सिबिलिटी (सीएसआर) को कानून अनिवार्य बनाया गया है। यह कानून व्यापारिक गतिविधियों से अर्जित धनलाभ में से कुछ भाग को सामाजिक रूप से व्यव करने के प्रावधान करता है। 01 अप्रैल, 2014 से यह कानून लागू है। अब इस कानून और इसके क्रियान्वयन के अनुभवों पर विचार करने की आवश्यकता के नई सीएसआर निगरानी नीति की जरूरत महसूस की जा रही है। यह कानून हमारे हजारों साल पुराने जीवन दर्शन की बुनियाद पर खड़ा है। यह ऐसी बुनियाद है जहां दान और परोपकार का उद्देश्य समाज के वास्तविक जरूरतमन्दों के लिए विकास और उत्कर्ष के अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए होता रहा है। यह कानून सिर्फ भारतीय कंपनियों पर ही लागू नहीं होता है बल्कि उन सभी विदेशी कंपनियों के पर लागू होता है जो भारत में कार्य करती हैं। कानून के अनुसार, एक कंपनी को जिसका सालाना नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये या सालाना इनकम 1000 करोड़ रुपये या वार्षिक मुनाफा 5 करोड़ रुपये का हो तो उसको सीएसआर पर खर्च करना जरूरी होता है। यह खर्च कंपनी के तीन साल के औसत लाभ का कम से कम दो प्रतिशत होना जरूरी है। 2014 से 2021 की अवधि में इस कानून के तहत 126938 करोड़ रुपये धन एकत्रित हुआ। यह रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत विकास, पोषण, ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में खर्च की गई। इसमें निर्गत बदलाव की आवश्यकता इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि देश में इस राशि का वितरण असमान है। तुलनात्मक रूप में ज्यादा वास्तविक जरूरतमंद क्षेत्रों के लिए इससे कई खास फायदा नहीं मिल पा रहा है। बेशक कानून इस राशि के व्यव के लिए औद्योगिक इकाइयों के स्थानीय क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है लेकिन यह भी तथ्य है कि भारत में समग्र विकास की गति भौगोलिक रूप से बहुत असमान है। महाराष्ट्र गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, और प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्य विकास के लगभग सभी संकेतकों पर उत्तर भारत के अन्य राज्यों से अभी भी अग्रणी हैं। सीएसआर के तहत खर्च के आंकड़े इस असमान विकास कम करने के स्थान पर बढ़ाते नज़र आ रहे हैं। अब तक व्यव की गति कुल सीएसआर राशि में 40 फीसदी तो केवल सात राज्यों में ही खर्च हुआ है। इसमें पैन इंडिया यानी एक साल हुए देशव्यापी आवंटन को भी जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा 60 फीसदी हो जाता जाता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 4023 करोड़ रुपये महाराष्ट्र में 18605 करोड़ रुपये, गुजरात में 6221 करोड़ रुपये, कर्नाटक में 7160 करोड़ रुपये तमिलनाडु में 5437 करोड़ रुपये, आंध्र प्रदेश में 5100 करोड़ रुपये एवं तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपये सीएसआर के तहत 2014 से अब तक व्यव किये गये हैं। यह ऐसे राज्य हैं जहां औद्योगिक विकास के सामानीय हृषि से भी जीवन स्तर समेत अन्य संकेतक देश के अन्य राज्यों से बहेतर हैं। इन राज्यों की कुल आबादी भी खर्च के अनुपात में समान नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा या पूर्वोत्तर के राज्यों में आधारभूत विकास से लेकर सामाजिक रूप से निवेश की आवश्यकता अत्यधिक है। तथ्य यह है कि 22 करोड़ का आबादी वाले उत्तर प्रदेश में गुजरात की तुलना में आधा यानी 328 करोड़ का फंड ही मिल सका। इस तरह बिहार में तो यह आंकड़ा मात्र 691 करोड़ ही हो पाया है। कमोबी मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा 1149 छत्तीसगढ़ में 1385, पश्चिम बंगाल में 2487 और झारखण्ड में 871 करोड़ रहा। सरकार ने कुछ संशोधन कर इस खर्च में रिसर्च और डेवलपमेंट को भी जोड़ा है लेकिन अभी इस दिशा में कोई ठोस कानून दिखाई नहीं दे रहा है। एक और विसंगति यह है कि बड़े घरानों ने अपने प्रभाव वाले एनजीओ एवं ट्रस्ट खड़े कर लिए हैं। यह ट्रस्ट

डॉ. अजय खेमरिया

01 अप्रैल, 2014 से  
यह कानून लागू है। अब  
इस कानून और इसके  
क्रियाव्यवन के अनुभवों  
पर विचार करने की  
आवश्यकता के नई  
सीएसआर निगरानी नीति  
की जरूरत महसूस की  
जा रही है।

राजनीति

यूनिवर्सिटीज, अस्पताल और कौशल विकास केंद्र संचालित करते हैं। यह एक तरह से केवल धन का डायवर्जन भर है। बेहतर होगा सरकार सीएसआर के लिए कुछ बड़े बुनियादी बदलाव सुनिश्चित करे। मसलन कुल धन का 75 फीसदी तो अभी तक शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी पर खर्च हुआ है। इन तीनों क्षेत्रों में सभी सरकारें पिछले 75 साल से पार्नी की तरह पैसा खर्च कर रही हैं। सीएसआर की राशि का इन क्षेत्रों में व्यय किया जाना असल में दोहराव भर लगता है। अच्छा होगा कि एक नियामक निकाय सीएसआर के लिए खड़ा किया जाय। देशभर की सीएसआर राशि एक स्थान पर संकलित हो। इस राशि के खर्च के लिए एक विशेषज्ञ पैनल हो। हर जिले में एक कौशल विकास केंद्र बनाया जाय। बड़ी कंपनियां यहां खर्च करें। इसी तर्ज पर फूट प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल जैसे प्रयोग अमल में लाए जा सकते हैं।



ट्रीट-ट्रीट

फेसबुक वॉल से

 Raj Kumar Singh ... X  
19 h · 

बोर्ड परीक्षाएँ चल रही हैं. यदि आपको रास्ते में छात्रों का वाहन, कार, बाइक, साइकिल खराब दिखे, कोई छात्र परेशान दिखे तो पूछ लें, हो सकता है वो परीक्षा केंद्र जाने के लिए परेशान हो. कुछ भूल गया हो? उसे केंद्र तक पढ़ुँचा दें. बच्चे पहली बार इस तनाव से गुजरते हैं. खास तौर से हाई स्कूल के. आपकी मदद उनके लिए बड़ा संबल होगा. आपको भी अच्छा लगेगा.

# चिंता का सबब बनती जा रही आत्महत्या की प्रवृत्ति

A black and white portrait of a man with dark hair and a mustache, wearing a dark jacket over a light-colored shirt.

योगेश कुमार गोयल

दरअसल कमाई कम होने  
या रोजगार नहीं होने के  
कारण लोगों में तनाव  
बहुत बढ़ गया है, जिससे  
बहुत से मामलों में  
पारिवारिक क्लेश पैदा  
होता है और  
परिणामस्वरूप आत्महत्या  
के मामले बढ़ रहे हैं।

दुनियादारी

संबंध और 1408 बीमारी के कारण हुई। एनसीआरबी के मुताबिक आत्महत्या की सर्वाधिक प्रवृत्ति महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में देखी गई है। केवल इन पांच राज्यों में ही देशभर में आत्महत्या के कुल मामलों में से 50.4 फीसदी मामले दर्ज हुए जबकि 49.6 फीसदी मामले 23 अन्य राज्यों और 8 केन्द्रशासित प्रदेशों में सामने आये। पिछले एक साल में उपरोक्त पांच राज्यों में क्रमशः 22207, 18925, 14965, 13500, 13056 लोगों ने आत्महत्या की, जो कुल मामलों का क्रमशः: 13.5, 11.5, 9.1, 8.2 और 8 फीसदी है। प्रति एक लाख की आबादी पर आत्महत्या के मामलों की राशीय दर हालांकि 12 रही लेकिन कुछ राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में स्थिति बेहद चिंताजनक है।



# KASHYAP'S DENTAL CLINIC

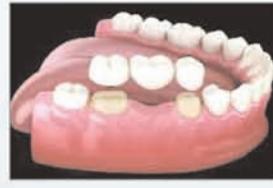


**Dr. Vaibhav Kashyap**

Oral & Dental Surgeon, C.c. Endodontist & Implantologist Certified Orthodontist, MIDA

"Smiles & More"

छात्र-छात्राओं के लिए  
50% की छूट



- ❖ आरसीटी
- ❖ पायरिया का ईलाज
- ❖ टेढ़े-मेढ़े दाँतों का ईलाज
- ❖ स्मार्टल डिजाइन
- ❖ इनविजिवल विलाप

## Facilities

- ❖ दंत रोपण
- ❖ फिक्स दाँत लगाना
- ❖ अत्यधुनिक मशीन और तकनीक के द्वारा ईलाज

## CHAMBER

SKYLINE - 4006, 4th Floor, Kadru, Opp. Dr. Lal's Hospital, Ranchi  
Contact No. : 9199533383, 7903835453  
Time : 9 am to 2 pm & 4 pm to 8 pm  
Sunday : 9 am to 2 pm  
E-mail : vaibhav.kashyap2011@gmail.com

## NEWS इन ब्रीफ

काबुल में आईएसकेपी के सैन्य प्रमुख की हत्या काबुल। इस्लामिक स्टेट

खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) के खुफिया और सैन्य प्रमुख काबुल में एक

अभियान के दौरान मारे गए, मीडिया में आई खबर में यह जानकारी दी गई। एक एक्सप्रेस ट्रिल्यून ने बताया- एक अलग ऑपरेशन में, अफगान तालिबान प्रशासन ने उच्च पदथ

आईएसकेपी अधिकारी को गिरफ्तार किया, जिसे आतंकवादी संगठन के उपकारीप्रमुख के रूप में काम करने के लिए जाना जाता है। आंपरेशन के विवरण के अनुसार, काबुल के खैर खाना, शरक-ए-जाकिनी की पहली गार्ड में खिलाफ गत भर के अपरेशन में दावा के दो सदस्य मारे गए।

**स्कूल के पास हुई गोलीबारी में दो लोग गंभीर रूप से घायल**

बर्लिन। उत्तर पश्चिम जर्मनी के बाणी में एक स्कूल के पास हुई गोलीबारी की विवरण में यह जानकारी दी गई। स्कूल के पास खिलाफ गत भर के अपरेशन में दावा के दो सदस्य मारे गए।

**किन गैंग जी20 बैठक में भाग लेने के लिए भारत आएंगे**

यहां तक कि जिला एवं सत्र अदालत ने मंगलवार को तोशखाना मामले में पाकिस्तान तहसील-ए-इसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। जिसे न्यूज़ ने बताया कि मामले की सुनवाई करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने फैसले की घोषणा की।

नई दिल्ली। चीन के विदेश मंत्री किन गैंग दिल्ली में जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए इस सपाह के अंत में भारत आएंगे, चीनी विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। पुलिस ने सीरीज़ शूट को गिरफ्तार कर लिया है और लोगों को अब कोई खतरा नहीं है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के हवाले से पुलिस ने कहा कि स्कूल भी अफेंडे नहीं हुआ है।

**किन गैंग जी20 बैठक में भाग लेने के लिए भारत आएंगे**

यहां तक कि जिला एवं सत्र अदालत ने मंगलवार को तोशखाना मामले में पाकिस्तान तहसील-ए-इसाफ (पीटीआई) और बैंकिंग अदालत ने न्यायिक परिसर में पेश होने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने फैसले की घोषणा की।

इससे पहले मंगलवार को आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) और बैंकिंग अदालत ने न्यायिक परिसर में पेश होने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने फैसले की घोषणा की।

पूर्व प्रधानमंत्री को उनके खिलाफ दावर निषिद्ध धन और आतंकवाद के मामले में जमानत मिली। एटीसी जज राजा जवाद ने आतंकी मामले की सुनवाई की और 100,000 रुपये के जमानत बांद जमा करने पर 9 मार्च तक खान को जमानत दे दी। इस बीच, न्यायाधीश रक्षांदा शाहीन ने निषिद्ध धन मामले में खान की जमानत की



एजेंसी। पटना

बिहार बजट 2023

पदों पर शिक्षकों की बहाली होगी।

गैरतत्व है कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

चौधरी ने बजट पेश किया, बजट 2023 में युवाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अवसर पर सूखुआती घोषणाओं के लिए एक से

दैरेन कहा कि बजट के सूखुआती घोषणाओं में ही युवाओं के लिए खुशखबरों की बात सामने आई।

वैसे कुछ दिन पहले पुलिस दिवस के अव



